आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 07 लखनऊ, गुरूवार 21 मई 2026 सा 27 मई 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी को भेंट की 'मेलोडी'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी समकक्ष ज र्जिया मेलोनी को मेलोडी ट फी का पैकेट भेंट किया। इस गिफ्ट के लिए मेलोनी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। इतालवी पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर १२ सेकंड की वीडियो क्लिप साझा की। जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिख रही हैं। इस क्लिप में वो कह रही हैं, "प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। ये टॉफियां हैं जो बहुत स्वादिष्ट हैं।" इसके बाद उनकी दाईं तरफ खड़े पीएम मोदी टॉफी का पैकेट उठाते हैं जिस पर लिखा है 'मेलोडी'। 'गिफ्ट' को कैमरे की तरफ दिखाने के बाद दोनों खिल खिलाकर हंस देते हैं। पीएम मोदी मंगलवार को इटली की आधिकारिक यात्रा पर रोम पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री ज र्जिया मेलोनी ने मंगलवार रात (स्थानीय समयानुसार) रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंचे हैं। मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफ र्म 'एक्स' पर लिखा, "रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त!", जिससे दोनों नेताओं के बीच अच्छी दोस्ती साफ दिखाई देती है। इससे पहले पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की

ओर से आयोजित डिनर में भी शामिल हुए। उन्होंने इस डिनर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफ र्म 'एक्स' पर साझा कीं। पीएम मोदी ने कहा कि वह मेलोनी के साथ बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश भारत–इटली संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, "रोम पहुंचने के बाद मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी से डिनर पर मिलने का मौका मिला, इसके बाद कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर विचारों का आदान–प्रदान किया। मैं आज होने वाली बातचीत का इंतजार कर रहा हूं, जिसमें हम भारत–इटली दोस्ती को और मजबूत करने पर बात करेंगे।" पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आगमन की जानकारी भी साझा की और बताया कि यह यात्रा भारत और इटली के रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोशल मीडिया प्लेटफ र्म 'एक्स' पर लिखा भारत–इटली रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर इटली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और इटली के बीच लंबे समय से बहुआयामी साझेदारी रही है। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाली है।

नीट पेपर लीक केस में शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी ५ दिन बढ़ी

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इस हाई–प्रोफाइल मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्य आरोपी माने जा रहे शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं, मामले में गिरफ्तार बाकी पांच आरोपियों को अदालत ने २ जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। दरअसल, सीबीआई ने पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार कुल छह आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इनमें महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से गिरफ्तार आरोपी शामिल हैं। कोर्ट में पेश किए गए आरोपियों में नासिक निवासी शुभम खैरनार, जयपुर के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल, गुरुग्राम के यश यादव तथा महाराष्ट्र के अहिल्या नगर निवासी धनंजय लोखंडे के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने कोर्ट से शुभम खैरनार की कस्टडी बढ़ाने की मांग की। एजेंसी का कहना था कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के साथ शुभम खैरनार का सामना कराना जरूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्र निक सबूतों को लेकर भी उससे आगे पूछताछ की जानी है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में आगे रिकवरी भी करनी है और जांच के सिलसिले में शुभम खैरनार को महाराष्ट्र लेकर जाना पड़ेगा। सीबीआई ने बाकी पांच आरोपियों, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे, को न्यायिक

हिरासत में भेजने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को २ जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। वहीं, शुभम खैरनार के वकील ने सीबीआई की कस्टडी बढ़ाने की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि सात दिनों की पूछताछ के दौरान सीबीआई को क्या मिला, यह एजेंसी को कोर्ट के सामने स्पष्ट करना चाहिए। नीट यूजी २०२६ पेपर लीक मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों और पूछताछ के बीच अब जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।

लखनऊ के न्यू देवा हॉस्पिटल में महिला की मौत पर बवाल, गलत खून चढ़ाने का आरोप

लखनऊ। राजधानी के कुर्सी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। मामला गुडंबा थाना क्षेत्र के कुर्सी रोड स्थित न्यू देवा हॉस्पिटल का है। जानकारी के अनुसार सीतापुर के तंबौर क्षेत्र की रहने वाली ३६ वर्षीय महिला पैर का ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला को गलत खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में आक्रोश

फैल गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया और ड क्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि घटना के बाद अस्पताल संचालक और संबंधित डॉक्टर मौके से फरार हो गए। स्थिति बिगड़ने की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस की गुडंबा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन की भूमिका और इलाज के दौरान बरती गई कथित लापरवाही की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

राजधानी के अधिवक्ताओं का 26 मई तक सामूहिक अवकाश

लखनऊ'। अधिवक्ता हितों एवं सम्मान की रक्षा हेतु आज दिनांक २० मई २०२६ को लखनऊ के अधिवक्ता साथियों की एक पंचायत (आम सभा) सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के पदाधिकारीगणों के नेतृत्व में आयोजित की गई। सभा में विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।१.दिनांक २६ मई २०२६ तक समस्त अधिवक्तागण सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। २.अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के संबंध में दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने का निर्णय लिया गया। ३.वजीरगंज थाने में अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज कथित झूठे मुकदमों को वापस लिए जाने हेतु शासन एवं प्रशासन से माँग की गई। आगामी रणनीति एवं आंदोलन की

रूपरेखा प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के साथ लखनऊ में आयोजित बैठक के उपरांत निर्धारित की जाएगी। हम समस्त अधिवक्तागण, सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के पदाधिकारीगणों के नेतृत्व एवं निर्णयों का पूर्ण निष्ठा एवं एकता के साथ पालन करेंगे।

सम्पादकीय

सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' की धूमय युवाओं की बेचौनी और बदलते विरोध प्रदर्शनों का संकेत

कॉकरोच वाली टिप्पणी पर जैसी प्रतिक्रिया हुई है, वह खासकर युवा वर्ग में गहराते असंतोष और उनमें फैल रही बेचौनी का संकेत है। युवाओं के बहुत हिस्से को संभवतः यह अहसास हुआ कि उनकी स्थिति को सचमुच कॉकरोच जैसा बना दिया गया है। इसलिए जगह–जगह पर खुद को क करोच बताते हुए विरोध जताने की अनपेक्षित घटनाएं हुई हैं। मसलन, लखनऊ में बेरोजगार नौजवान सड़क पर सचमुच क करोच की तरह रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के दफ्तर की ओर विरोध जताने जाते देखे गए। दिल्ली में 'मैं क करोच हूं' की तख्तियां लगाए नौजवान यमुना की सफाई करने गए। और कुछ नौजवानों ने तो 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से एक ऑनलाइन दल की ही शुरुआत कर दी है। बताया जाता है कि दो दिन के अंदर ५० हजार से ज्यादा नौजवानों ने इस पार्टी ऑनलाइन सदस्यता ले ली। इस पार्टी ने अपना प्रतीक चिह्न और अपने मकसद को बताते हुए एक गाने का वीडियो जारी किया, तो वो वायरल हो गया। अब इस पार्टी ने जेनरेशन– जेड के नौजवानों का ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का इरादा जताया है। पार्टी का घोषणापत्र उन मुद्दों से भरा पड़ा है, जिनसे आज के नौजवान व्यग्र दिखते हैं। मसलन, दल–बदल करने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर २० साल की रोक, 'गोदी मीडिया' के एंकरों के बैंक खातों की जांच, एक भी वैध मतदाता का नाम कटने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की यूएपीए के तहत गिरफ्तारी, प्रधान न्यायाधीश पद से रिटायर जजों के राज्यसभा में नामांकन पर रोक आदि जैसे वादे इसका हिस्सा हैं। बेशक, ये पहल एक तरह का व्यंग्य है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में काउंटर कल्चर आंदोलनों की रही प्रभावशाली भूमिका को देखते हुए इसके महत्त्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अलग–अलग दौर में अवसरहीनता एवं अंधकारमय भविष्य से जूझ रहे नौजवान व्यंग्य और उलटबासियों का सहारा लेते रहे हैं। इनके जरिए वे व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। आज जब सोशल मीडिया वैचारिक एवं राजनीतिक संघर्ष का रण–क्षेत्र बना हुआ है, इस तरह की अभिव्यक्तियों का प्रभाव और दूरगामी हो गया है। शासक समूहों को इसमें छिपे संदेशों को अवश्य समझना चाहिए।

समन्वित प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में लाएं कमीः अधिकारियों से बोले सीएम योगी, जनजागरुकता अभियान चलाने के दिए निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें देश और राज्य दोनों के लिए बड़ी क्षति हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को सड़क सुरक्षा संबंधी उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा और अलीगढ़ सहित विभिन्न जनपदों में हाल में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जनवरी २०२६ से अप्रैल २०२६ तक सड़क दुर्घटनाओं में २१ प्रतिशत तथा मृतकों की संख्या में २२ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। योगी ने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती हैं, इसलिए सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 'टॉप टू बॉटम' हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए तथा शासन स्तर पर पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें चिन्हित कर कारणों का विश्लेषण किया जाए और समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवरस्पीडिंग और नशे की हालत में वाहन चलाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर नियमित बैठक करें। अवैध वाहनों का संचालन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है तथा अवैध वाहन स्टैंड तत्काल हटाए जाएं। सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारी फील्ड में उतरकर कार्य करें तथा आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों की जवाबदेही तय की

जाए। परिवहन निगम केवल फिटनेसयुक्त बसों का संचालन सुनिश्चित करे तथा चालकों और परिचालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अपने वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें और बिना फिटनेस वाले वाहन सड़क पर न चलें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन वाहनों का बार–बार चालान हो रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिसमें लाइसेंस या परमिट निरस्तीकरण भी शामिल हो। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौराहों, टोल प्लाजा, व्यस्त मार्गों और अन्य प्रमुख स्थलों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा होर्डिंग्स के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा मानकों के पालन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नियमित पेट्रोलिंग तथा एंबुलेंस की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर समयबद्ध तरीके से उनका सुधार करने, आवश्यक स्थानों पर साइनेज लगाने तथा चौराहों पर टेबलटॉप स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा कोष के तहत २५ चारपहिया इंटरसेप्टर, ६२ दोपहिया इंटरसेप्टर और ८२ स्पीड लेजर गन जनपदों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी ७५ जिलों के ४८७ क्रिटिकल पुलिस थानों पर 'जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना' लागू की गई है, जिसके तहत गठित ५७३ क्रिटिकल क रिडोर टीमों ने पिछले चार महीनों में ५६६ लोगों की जान बचाई है।

गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था हो सुनिश्चित : दीपक कुमार कृषि उत्पादन आयुक्त

लखनऊ। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार ने लेखपाल भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा–२०२६ की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों परीक्षाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर सतर्कता एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाए। जिन जनपदों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि कि केन्द्र अधीक्षकों, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समुचित एवं गहन प्रशिक्षण कराया जाए, ताकि परीक्षा संचालन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही की संभावना न रहे। उन्होंने गोपनीय सामग्री की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कोषागार से प्रश्नपत्र एवं अन्य गोपनीय सामग्री की निकासी निर्धारित केन्द्र एवं सीरिज के अनुसार ही सुनिश्चित की जाए तथा सामग्री समयबद्ध तरीके से परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाई जाए। अभ्यर्थियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग को पूरी गंभीरता के साथ की जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि परीक्षा के दौरान रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की अधिक आवाजाही रहेगी, इसलिए उनकी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। उन्होंने परीक्षा तिथियों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए आवश्यकतानुसार ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती करने तथा सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय रखने पर भी बल दिया गया। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डों एवं परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार होल्डिंग एरिया बनाए जाएं तथा वहां पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केन्द्रों के निकटवर्ती अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए।

अस्पतालों में ओआरएस सहित आवश्यक औषधियों की उपलब्धता होनी चाहिए।दउन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान जनपद एवं राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से निरंतर निगरानी रखी जाए तथा नकल, प्रतिरूपण अथवा किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस. एन. साबत ने बताया कि लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा २१ मई, २०२६ को प्रातः १० बजे से दोपहर १२ बजे तक प्रदेश के ४४ जनपदों के ८६१ परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल ३,६६,७१२ अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं झांसी जनपद में १० हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। उत्तर प्रदेश बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा–२०२६ के आयोजक बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० मुकेश पाण्डेय ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा के लिए ४,४४,६५८ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि वर्ष २०२५ में ३,४४,५४६ एवं वर्ष २०२४ में २,२३,३८४ आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रदेश के ७२ जनपदों के १०११ परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी ६१ प्रतिशत तथा पुरुष अभ्यर्थियों की भागीदारी ३६ प्रतिशत है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर एवं आगरा में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली प्रातः ९ बजे से अपराह्न १२ बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न २ बजे से सायं ५ बजे तक संचालित होगी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा एआई इनेबल्ड सर्विलांस सिस्टम आधारित कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की लाइव निगरानी की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से किसी भी प्रकार की अनधिंत गतिविधि, नियंत्रण कक्ष अथवा निर्धारित क्षेत्रों में अनुमत संख्या से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति, निरीक्षकों की गतिविधियों में असामान्यता, भीड़, विवाद अथवा परीक्षा समय से पूर्व या बाद में कक्षाओं में होने वाली गतिविधियों पर स्वतः अलर्ट प्राप्त होगा। दोनों पालियों की परीक्षा के दौरान सभी केन्द्र अधीक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक एवं फेस रिकग्निशन आधारित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री एम.पी.अग्रवाल, एडीजी एलओ श्री अमिताभ यश, सचिव उच्च शिक्षा श्री अमृत त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहतः खरीफ-२०२६ में ५०: अनुदान पर मिलेंगे प्रमाणित बीज, ३१ मई तक करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ–२०२६ सीजन के लिए किसानों को राहत देते हुए ५० प्रतिशत अनुदान पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की बड़ी पहल की है। प्रदेश सरकार ने

सामान्य, प्रदर्शन और मिनीकिट योजना के तहत इस वर्ष कुल १ लाख ६६ हजार ६१० कुंतल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधि ाकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में ३१ मई तक सभी विक्रय केंद्रों पर बीज पहुंच जाने चाहिए, ताकि किसानों को बुवाई के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। कृषि मंत्री ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ७५,४२६ कुंतल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि २,६३६ कुंतल बीज किसानों में वितरित भी किए जा चुके हैं। उन्होंने किसानों से जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि समय रहते आवेदन करने पर किसानों को आसानी से अनुदान का लाभ मिल सकेगा। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य ८० हजार कुंतल निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले अब तक ६४,२२८ कुंतल धान बीज उपलब्ध हो चुका है और २,६३४ कुंतल बीज किसानों को वितरित भी किया जा चुका है। इसके अलावा तिलहन और दलहन फसलों के लिए भी बड़े पैमाने पर बीज वितरण की तैयारी की गई है। मूंगफली के लिए ५७,४४६ कुंतल, उड़द के लिए २३,६५८ कुंतल, अरहर के लिए २१,२२५ कुंतल, मूंग के लिए ३,६४६ कुंतल, तिल के लिए ३,८२७ कुंतल और सोयाबीन के लिए २,६६६ कुंतल बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश सरकार मोटे अनाज यानी श्री अन्न को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दे रही है। इसके तहत ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, काकुन और कुटकी जैसी फसलों के बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बाजरा के लिए १,६७२ कुंतल और रागी के लिए १,५०० कुंतल बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। बीज वितरण का कार्य कृषि विभाग के साथ सहकारिता विभाग, आईएफएफडीसी, एचआईएल और बीबीएसएसएल के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। इनमें अकेले कृषि विभाग को १,८६,६६० कुंतल बीज वितरण का लक्ष्य दिया गया है। विभाग अब तक ७४,२०४ कुंतल बीज उपलब्ध करा चुका है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे ५० प्रतिशत अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द पर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि खरीफ की बुवाई समय पर और सुचारु रूप से पूरी की जा सके। बैठक में टीएम त्रिपाठी तथा अनिल पाठक भी मौजूद रहे।

एसटीएफ और साइबर टीम की बड़ी कार्रवाईः शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ८० लाख की ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। विभिन्न कंपनियों और शेयर बाजार में निवेश कर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करीब ८० लाख

रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफ र्म के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। एसटीएफ द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिसमोर धाकड़ और पवन कुमार तिवारी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं। इन्हें थाना हबीबगंज क्षेत्र, भोपाल से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि एक संगठित गिरोह शेयर बाजार और विभिन्न कंपनियों में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सत्यसेन यादव के निर्देशन में टीम गठित कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफ र्म, फर्जी एप्लीकेशन और व्हाट्सएप क ल के माध्यम से लोगों से संपर्क करता था। आरोपी निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों को रकम निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे। जब पीड़ित पैसा ट्रांसफर कर देते थे, तो गिरोह के सदस्य फर्जी बैंक खातों में रकम मंगाकर उसे अलग–अलग खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। एसटीएफ के अनुसार गिरोह द्वारा साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने और रकम को विभिन्न खातों में भेजने का नेटवर्क भी संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी फर्जी दस्तावेजों और विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। मामले में थाना साइबर क्राइम लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१८(४), ३१६(२) बीएनएस और आईटी एक्ट की धारा ६६डी के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय होकर बड़ी संख्या में लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है।

एसटीएफ को बड़ी सफलताः ५० हजार का इनामी पशु तस्कर राजदेव शर्मा प्रतापगढ़ से गिरफ्तार

लखनऊ/प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने चंदौली जनपद में दर्ज पशु तस्करी और गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े मामले में फरार चल रहे ५० हजार रुपये के इनामी अपराधी राजदेव शर्मा को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना चंदौली में मुकदमा अपराध संख्या २७६ २४ के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा ४२६ तथा गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। गिरफ्तार आरोपी राजदेव शर्मा मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के जंघोरा थाना क्षेत्र के पदनाथपुर गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वह महाराष्ट्र के मुंबई में रह रहा था। एसटीएफ को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि आरोपी प्रतापगढ़ के नवाबगंज क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर एसटीएफ नोएडा यूनिट ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार दोपहर करीब एक बजे अहिमनगंज फ्लाईओवर के पास उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष २००८ से महाराष्ट्र में वाहन चलाने का काम करता था। वर्ष २०२१ में उसने एक ट्रक खरीदा और बाद में कुछ लोगों के संपर्क में आकर पशु तस्करी के धंधे में शामिल हो गया। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पशुओं को बिहार

के रास्ते पश्चिम बंगाल तक पहुंचाता था। एसटीएफ के अनुसार ३१ जनवरी २०२४ को आरोपी के वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पशु तस्करी की जा रही थी। इस दौरान चंदौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि आरोपी फरार हो गया था। तभी से उसकी तलाश की जा रही थी और उस पर ५० हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की अन्य आपराधिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को चंदौली पुलिस के हवाले कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लखनऊ पहुंचे, अपर्णा यादव के आवास जाकर जताई शोक संवेदना

लखनऊ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवार से मुलाकात कर दिवंगत प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख जताया और परिजनों को ढांढस बंधाया। बताया जा रहा है कि मोहन यादव ने इस दौरान परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनके लखनऊ आगमन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल बनी रही। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक भी मौके पर मौजूद रहे। शोक संवेदना प्रकट करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव वापस रवाना हो गए।

सीको कॉलेज ऑफ फार्मेसी लखनऊ में जॉब फेयर का आयोजन

लखनऊ। सीको कॉलेज आफ फार्मेसी में मैक्लिआड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा १८ मई २०२६ को जाब फेयर का आयोजन किया गया जिसमें कॉलेज के बी.फार्मा, डी.फार्मा और आईटीआई के छात्रों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। मैक्लिआड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के एचआर टीम द्वारा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद लगभग ४० छात्रों का चयन विभिन्न पदों पर किया गया।इस जॉब फेयर के आयोजन में कॉलेज के फैकल्टी व अन्य स्टाफ मेंबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस जॉब फेयर में उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न फार्मेसी क लेजों के छात्र–छात्राओं ने भी भाग लिया। कॉलेज के फाउंडर सतीश बत्रा, निदेशक डॉ. मुकेश कुमार दुबे, मैनेजर रक्षपाल सिंह व प्रवक्ता डी. पी. यादव ने चयनित छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कंपनी का धन्यवाद व्यक्त किया।

रायबरेली में राहुल गांधी के बिगड़े बोल, पीएम मोदी और अमित शाह पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

रायबरेली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के लोधवारी गांव में आयोजित 'बहुजन स्वाभिमान सभा' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए दोनों को गद्दार कहा और देश बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और संविधान की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में देश को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हों ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और केंद्र सरकार की नीतियों का असर आम जनता पर पड़ेगा, जिससे महंगाई तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ–साथ दाल और चावल जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता को सोना न खरीदने और विदेश यात्रा से बचने

की सलाह देते हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग खुद आलीशान विमानों से विदेश दौरे करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों को खाद जैसी जरूरी चीजों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश की जनता की आवाज और अधिकारों का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से संविधान की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट आने पर केंद्र सरकार जनता को राहत देने में विफल साबित होगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कोविड महामारी और नोटबंदी के दौरान जिस तरह सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे, उसी तरह आने वाले समय में भी जनता कठिन हालात का सामना कर सकती है। राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर १६ मई को रायबरेली पहुंचे थे। बुधवार को वह अमेठी भी पहुंचे, जहां उन्होंने संजय गांधी अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की।

सितंबर में भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल सितंबर में भारत आएंगे। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुतिन भारत आ रहे हैं। एक साल के अंदर यह उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी। सरकार की ओर से मंगलवार को बताया गया कि रूसी राष्ट्रपति १२ और १३ सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पुतिन पिछले साल दिसंबर में भारत यात्रा पर आए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया था। गौरतलब है कि भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। पिछले दिनों ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवारोव शामिल हुए थे। ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका शुरुआती सदस्य देश हैं और इनके अलावा मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य भी शामिल हो चुके हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी भी इस साल रूस

के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले पुतिन दिसंबर २०२५ में भारत आए थे। उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ २३वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। २०२५ का दौरा इसलिए खास माना गया था, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा था। इससे पहले वह आखिरी बार २०२१ में नई दिल्ली आए थे।

फिर बढ़ी पेट्रोल, डीजल की कीमत

नई दिल्ली। पांच दिन के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। मंगलवार को पेट्रोल के दाम में ८७ पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में ९१ पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में तीन–तीन रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही सीएनजी की कीमत में दो रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। इसके दो दिन बाद सीएनजी की कीमत में फिर एक रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। इस तरह पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद से पेट्रोल ३.८७ रुपए और डीजल ३.९१ रुपए महंगी हुई है, जबकि सीएनजी की कीमत तीन रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में एक बार में ९३४ रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद दिल्ली में १९ किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत ३१ सौ रुपए से ज्यादा हो गई। बहरहाल, मंगलवार को हुई बढ़ोतरी के बाद देश के १५ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल एक

सौ रुपए लीटर के ज्यादा के दाम पर बिक रहा है। वहीं १७ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में डीजल का दाम ९० रुपए लीटर से ज्यादा है। केरल व तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत १११ रुपए लीटर से ज्यादा है, जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश में ११० रुपए लीटर से ज्यादा दाम पर पेट्रोल बिक रहा है। गौरतलब है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से खाड़ी देशों से होने वाली तेल व गैस की आपूर्ति लगभग बंद है। इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम एक सौ डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है। भारत में चल रहे चुनावों की वजह से सरकार ने तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी थीं। लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम और बढ़ेंगे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पिछले दिनों बताया कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन एक हजार करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। तीन–तीन रुपए कीमत बढ़ाने के बावजूद रोजाना का घाटा साढ़े सात सौ करोड़ रुपए है। इसके बावजूद उन्होंने पेट्रोलियम सेक्टर को बेल आउट पैकेज देने की संभावना से इनकार किया।

'देश में महंगाई, पीएम मोदी मेलोनी को खिला रहे टॉफियां', राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर तीखा हमला बोला। अमेठी में उन्होंने पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री ज र्जिया मेलोनी की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि मोदी जी

'टॉफियां खा रहे हैं।' अमेठी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि युवा डिप्रेशन में हैं, नीट का पेपर रद्द हो गया है, गैस और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, और मोदी जी जॉर्जिया मेलोनी के साथ टॉफियां खा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात पर की। पीएम मोदी इटली के दौरे पर हैं और उन्होंने मेलोनी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट किया, जिसका वीडियो खुद इटली की पीएम ने शेयर किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं, इससे पहले रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और आरएसएस को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अंबेडकर को याद किया जाता है और लोग उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब आरएसएस खुलेआम अंबेडकर के संविधान पर हमला करता है और उसे तार–तार कर देता है, तो वही लोग, जो उनकी प्रतिमा के सामने सिर झुकाते हैं, उनकी विचारधारा को भूल जाते हैं और उसकी रक्षा नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि जब आरएसएस के लोग इसी संविधान को आपके सामने ही फाड़कर फेंक देते हैं, तो आप चुप रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संविधान में आपकी आवाज और आपका खून शामिल है। इसकी रक्षा करना और इसे बचाना आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आपसे कहते हैं कि आप विदेश यात्रा न करें, सोना न खरीदें और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें। आने वाले समय में किसानों को शायद खाद भी उपलब्ध न हो। आर्थिक तूफान आने वाला है। आप बस कुछ ही महीनों में देखेंगे कि महंगाई कहां पहुंच जाएगी, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कहां पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री खुलेआम कहते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, और फिर खुद हजारों करोड़ रुपए के विमान में विदेश यात्रा करते हैं और आप लोग चुप रहते हैं।

आवारा कुत्तों पर फैसला नहीं बदलेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने आदेश को बदलने से इनकार कर दिया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। अदालत ने कहा कि लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है और गरिमा के साथ जीने में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को इस मसले पर आखिरी फैसला दिया और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर नवंबर २०२५ में दिए गए निर्देश ही लागू होंगे। साथ ही यह भी कहा कि जो अधिकारी इनका पालन न करें, उन पर अवमानना का केस चले। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर २०२५ में स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे जैसे सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़ें, नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं न छोड़ें। ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखें। अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। इसके बाद कई ड ग लवर्स और एनजीए ने इन निर्देशों को रद्द कराने के लिए कई याचिकाएं दाखिल की थीं। अदालत ने सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

भारत–नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, १६ मई को तीसरे भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून का सम्मान के नरजिए से भारत और नॉर्डिक देशों को स्वाभाविक साझेदार हैं। नॉर्डिक देशों में न र्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन शामिल हैं। इन देशों के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में यह साझेदारी और आगे बढ़ेगी। इससे पहले मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्टेरी ओर्पो और आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुनॉम्योल फ्रॉस्टाडोटिर से भी

मुलाकात की। इस सम्मेलन का मकसद भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करना था। प्रधानमंत्री मोदी इस समय पांच देशों के दौरे पर हैं। न र्वे उनका चौथा पड़ाव है। इससे पहले वह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं। न र्वे से प्रधानमंत्री इटली के दौरे पर जाएंगे। बहरहाल, भारत–न र्डिक सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्टेरी अ रपो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रिन्यूएबल एनर्जी और टिकाऊ विकास जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों देशों ने साल २०३० तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया।

ब्रिटिश विदेश मंत्री की चेतावनी, 'होर्मुज बंद होने से खाद्य संकट की ओर बढ़ रही दुनिया'

नई दिल्ली। ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेत कूपर ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमः मध्य बंद रहने की वजह से दुनिया "वैश्विक खाद्य संकट की ओर बढ़ रही है। मंगलवार को ग्लोबल पार्टनरशिप्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि खाड़ी देश उर्वरक के बड़े वैश्विक आपूर्तिकर्ता हैं और ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण समुद्री आवागमन बाधित होने से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी, पहली तिमाही) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अगर ईरान संघर्ष इस साल के मध्य तक खत्म नहीं हुआ, तो लगभग ४.५ करोड़ और लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का शिकार हो सकते हैं। कूपर ने कहा दुनिया एक वैश्विक खाद्य संकट की तरफ बढ़ रही है। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि एक देश अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बाधित कर दे और इसकी वजह से करोड़ों लोग भूखे रहने को मजबूर हो जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि होर्मुज को बंद रखने से वैश्विक खाद्य और ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इससे जीवनयापन की लागत भी बढ़ रही है। ब्रिटेन ने इस जलमार्ग को तुरंत और बिना किसी रोक–टोक के खोलने की मांग दोहराई है। साथ ही "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मल्टीनेशनल मिशन" को आगे बढ़ाने की बात भी कही है, ताकि समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखा जा

सके। उन्होंने कहा कि यह संकट केवल विकासशील देशों को ही नहीं, बल्कि विकसित देशों, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते वैश्विक साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नई रणनीति की जरूरत महसूस हो रही है। पीएम मोदी मार्च २०२६ की तिमाही खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया था कि मध्य पूर्व संघर्ष जारी रहा तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए तेल और उर्वरकों की आपूर्ति बाधित होने से वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि यदि यह संघर्ष जारी रहा, तो २०२६ के मध्य तक अतिरिक्त ४.५ करोड़ लोग भुखमरी और खाद्य संकट का सामना कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने चेतावनी दी कि ऊर्जा कीमतों में झटके और व्यापारिक मार्गों में बाधा आने से आगामी महीनों में खाद्य कीमतों में और तेज बढ़ोतरी हो सकती है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी से मार्च २०२६ के बीच उर्वरकों की कीमतों में भारी उछाल आया है। खासकर यूरिया की कीमतों में एक महीने में लगभग ४६ प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और पहले से ही महंगे उत्पादन खर्च हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष और जलवायु संकट अभी भी दुनिया के कई क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा के सबसे बड़े कारण बने हुए हैं। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में ८.७ करोड़ से अधिक लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में २०२६ के मध्य तक लगभग ५.२ करोड़ लोगों के गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझने की आशंका जताई गई थी।

उपमुख्यमंत्री से मिले भाजपा नेता रवि गुप्ता, ओवरब्रिज निर्माण की मांग

पलिया कलां, खीरी।' भाजपा नेता रवि गुप्ता ने लखनऊ में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके आवास पर मुलाकात कर पलिया क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। 'बाढ़ में कट जाता है संपकर्ू' रवि गुप्ता ने बताया कि बाढ़ के दौरान पलिया–लखीमपुर मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाता है। आम जनता, मरीजों और आपात सेवाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने अतरिया रेलवे क्र सिंग से शारदा पुल के पहले तक ओवरब्रिज निर्माण की मांग की। कहा कि ओवरब्रिज बनने से संकट

बाढ़ में बंद होता पलिया-लखीमपुर मार्ग, अतरिया से शारदा पुल तक ओवरब्रिज बनाने का ज्ञापन

के समय भी आवागमन सुचारु रहेगा और लाखों लोगों को राहत मिलेगी। 'शहर की क्र सिंग पर भी ओवरब्रिज की मांगरू' इसके अलावा पलिया शहर की दोनों रेलवे क्र सिंग पर छोटे ओवरब्रिज बनवाने की मांग भी रखी। गुप्ता ने कहा कि गन्ना सीजन में भारी जाम लगने से स्कूली बच्चों, व्यापारियों और क्षेत्रीय जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में जनहित को देखते हुए जल्द कार्यवाही की मांग की गई है। उपमुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है।

ट्रंप ने हमला टाला, ईरान सुपारी दे रहा

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला टाल दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान किया था। लेकिन बाद में उन्होंने कई खाड़ी देशों का नाम लेते हुए कहा कि उनके कहने पर हमला टाल दिया है। दूसरी ओर ईरान संसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुपारी जारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ईरान की संसद में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने वालों को पांच सौ करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम देने वाला बिल लाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रहा है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है, 'इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई' नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियन ने कहा कि संसद जल्दी ही इस बिल पर वोटिंग कर सकती है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे देशों के नेताओं ने बातचीत को मौका देने के लिए दो से तीन दिन का समय मांगा था। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के नेताओं को भरोसा है कि ईरान के साथ ऐसा समझौता हो सकता है, जिसे अमेरिका और पश्चिम एशिया के अन्य देश स्वीकार कर सकें।

हालांकि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष महमूद नबावियन ने चेतावनी दी कि अगर ईरान या उसके नेताओं पर फिर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि उन अरब देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने सफाई देते हुए कहा है कि दूसरे देशों के साथ बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है। उन्होंने साफ किया कि ईरान अपनी संप्रभुता और कानूनी अधिकारों से पीछे हटे बिना बातचीत जारी रखेगा।

कोतवाली गोला पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गोला गोकर्णनाथ खीरी, क्षेत्राधिकारी गोला रमेश कुमार तिवारी के कुशल मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गोला अम्बर सिंह के नेतृत्व में थाना गोला पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त हरपाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह उम्र करीब २० वर्ष निवासी ग्राम चौरठिया थाना गोला खीरी को एक अदद अवैध देशी तमंचा ३१५ बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस ३१५ बोर, के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त हरपाल सिंह उपरोक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० २०४/२०२६ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट पंजींत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। वही अभियुक्त गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम मे उप निरीक्षक प्रवीण कुमार, आरक्षी संजय कुमार मिश्र प्रमुख रूप से सामिल रहे।

'चौराहे पर पसरा अंधेरा, बंद पड़ी मर्करी लाइट बनी हादसे की वजह'

लखीमपुर–खीरी। फूलबेहड़ ब्लॉक के ओदरहना क्षेत्र में महेवा चौकी के पास स्थित मुख्य चौराहे पर अंधेरे का साम्राज्य है। चौराहे के बीचों–बीच लगी मर्करी लाइट महीनों से बंद पड़ी है। दोनों प्रमुख मार्गों के मिलन बिंदु पर स्थित यह चौराहा रात होते ही अंधेरे में डूब जाता है। यह व्यस्ततम मार्ग है जहां दिन–रात भारी भीड़–भाड़ रहती है। अंधेरे के कारण राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पार करने में जान जोखिम में डालनी पड़ती है। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौराहे पर प्रकाश व्यवस्था ठप होने से आपराधिक घटनाओं का भी खतरा बढ़ गया है। रात में आने–जाने वालों की पहचान मुश्किल हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर समस्या के बावजूद बिजली विभाग पूरी तरह मौन है। विभागीय अधिकारियों ने अब तक लाइट ठीक कराने की कोई पहल नहीं की है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग से जनहित में तत्काल चौराहे की मर्करी लाइट दुरुस्त कराने की मांग की है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके।

ब्रिक्स समिट 2026 : रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगम

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत के दौरे पर आने वाले हैं। भारत साल २०२६ में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति इस समिट में शामिल होने के लिए सितंबर २०२६ में भारत पहुंचेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफ र्म एक्स पर क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से जानकारी दी है कि व्लादिमीर पुतिन १२–१३ सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सालभर के अंदर दूसरी बार भारत के दौरे पर आने वाले हैं। भारत ने इस साल १३ जनवरी २०२६ को ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली थी। १४ जनवरी के आसपास भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समिट से जुड़े आधिकारिक थीम, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया था। इससे पहले पुतिन दिसंबर २०२५ में दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और २३वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। दोनों देशों ने आपसी संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदला। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और

मजबूत करने के लिए अपना समर्थन दोहराया। भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व ने इस लंबे समय से चले आ रहे दोनों देशों के संबंध की खासियत पर जोर दिया, जो आपसी भरोसे, एक–दूसरे के खास राष्ट्रीय हितों का सम्मान और रणनीतिक मेल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साझा जिम्मेदारियों वाली बड़ी ताकतों के तौर पर यह जरूरी संबंध वैश्विक शांति और स्थिरता का सहारा बना हुआ है। इसे बराबर और कभी न बंटने वाली सुरक्षा के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समिट के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीतिक और रणनीतिक, सैन्य और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक, न्यूक्लियर, स्पेस, संसेंति, शिक्षा और मानवीय सहयोग समेत कोअ परेशन के सभी क्षेत्र में फैले कई तरह के आपसी फायदे वाले भारत–रूस संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी ने संतुलित और सस्टेनेबल तरीके से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के अपने क मन एम्बिशन को फिर से कन्फर्म किया, जिसमें रूस को भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाना, औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना, नई तकनीक और निवेश साझेदारी बनाना, खासकर उच्च स्तरीय तकनीकी क्षेत्र में और अधिक सहयोग के नए रास्ते और तरीके ढूंढना शामिल है। उन्होंने २०३० तक भारत–रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रोग्राम २०३० को अपनाने का स्वागत किया।

व्यापार समझौतों से भारत–नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में नए स्वर्णिम युग की शुरुआतः पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरे इंडिया–न र्डिक समिट में शामिल हुए। समिट में सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी और शांतिपूर्ण और खुशहाल भविष्य के लिए सहयोग को मजबूत पर जोर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस मीट को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र, कानून के नियम और बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता भारत और न र्वे को एक नेचुरल साझेदार बनाता है। दोनों देशों ने पश्चिम एशिया और वैश्विक तनाव के मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा आज भारत–नॉर्डिक समिट में शामिल होने पर मुझे खुशी हो रही है। इस समिट का आयोजन करने के लिए राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं। इस समिट में मैं सभी नॉर्डिक नेताओं का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र, कानून के नियम और बहुपक्षवाद के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें नेचुरल साझेदार बनाती है। आठ वर्ष पहले हमने नॉर्डिक देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा और गति देने के लिए इस फॉर्मेट का गठन किया।" उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की है। १० वर्षों में हमारा द्विपक्षीय व्यापार चार गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के निवेश फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक में न र्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग २०० फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते व्यापार और निवेश में भारत की ग्रोथ स्टोरी ने योगदान दिया है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई और हजारों नई नौकरियां बनाई हैं। इस

मजबूत नींव पर अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल किए हैं। पीएम मोदी ने कहा अक्टूबर २०२५ से न र्वे, आइसलैंड और अन्य ईएफटीए देशों के साथ हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी लागू की है। कुछ ही महीने पहले हमने भारत–ईयू एफटीए किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार हैं। इन व्यापार समझौतों से हम भारत–नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने भारत और नॉर्वे के संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप देने का निर्णय लिया है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ग्रीन टेक्नोलॉजी साझेदारी से हम आइसलैंड की जीरो थर्मल इंफिसियरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोन मी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों के मैरिटाइम में सस्टेनिबिलिटी की विशेषज्ञता को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। इस यूनिक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल तकनीक, डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हिलटेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए विश्वसनीय समाधान विकसित करेंगे। भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन भी हैं। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप, लैब्स इकोसिस्टम के बीच लिकेज बढ़ाएंगे। हम आर्कटिक और पोलर रिसर्च में अपना सहयोग और गहरा करेंगे। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्किल डेवलपमेंट और मोबिलिटी के नए अवसर सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा हमने वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक नियम आधारित ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि बहुपक्षीय संस्थानों का रिफ र्म आवश्यक और तुरंत जरूरी भी है।

सवालों से घबरा कर भागे पीएम- राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नॉर्वे की एक पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के बाद हुए विवाद को लेकर राहुल गांधी ने मोदी की आलोचना की है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है, तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की भी कोई बात नहीं है'। गौरतलब है कि नॉर्वे में एक महिला पत्रकार हेली लिंग ने साझा प्रेस ब्रीफिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा था। हालांकि वे इसका जवाब दिए बगैर चले गए थे। राहुल ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने हेली की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मोदी के पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं देने से भारत की छवि पर असर पड़ा है। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के साथ साझा प्रेस ब्रीफिंग की थी। ब्रीफिंग के बाद मोदी और जोनास गार जाने लगे तब हेली लिंग ने पूछा, 'पीएम मोदी आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं देते'। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हेली ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर कर लिखा, 'नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है, जबकि भारत १५७वें नंबर पर है। वह इस मामले में फिलीस्तीन, एमीराट्स और क्यूबा से मुकाबला कर रहा है'। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने १८ मई को हेली लिंग की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय दूतावास प्रधानमंत्री के दौरे पर एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है और वे वहां आकर अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेली लिंग ने वहां भारत में मानवाधिकार की स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा, 'हम भारत पर भरोसा क्यों करें? भारत में जो हो रहा है, क्या उसे रोका

जाएगा? क्या प्रधानमंत्री कभी भारतीय प्रेस के कठिन सवालों का जवाब देंगे'? विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने इनका जवाब देने की बजाय भारत की पांच हजार साल की सभ्यता का हवाला दिया और संप्रभुता की बात कही। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। सिबी जॉर्ज ने कहा, 'कोविड महामारी के दौरान भारत ने दूसरे देशों की मदद की और वैक्सीन पहुंचाई। यही भरोसे की असली वजह है। बाद में हेली लिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने और उनके सहयोगी ने मानवाधिकार और भारत पर भरोसे से जुड़े सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हें सीधे जवाब नहीं मिले। भारतीय अधिकारियों ने कोविड, योग और भारत की उपलब्धियों की बातें ज्यादा कीं।

विद्या निकेतन में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम संपन्न

गोला गोकर्णनाथ खीरी। दिनांक २०/०५/२०२६ को स्थानीय विद्यालय विद्या कुंवरि स्मारक सरस्वती विद्या निकेतन इण्टर कॉलेज, गोला गोकर्णनाथ–खीरी में दैनिक जागरण समाचार समूह की ओर से हाईस्कूलध इण्टरमीडिएट परीक्षा २०२६ में विद्यालय के टॉप ५ मेधावी छात्र/छात्राओं को श्री विकास शुक्ल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इण्टरमीडिएट में सम्मानित होने वाले छात्र/छात्रायें रिया वर्मा – ८७.८०:, वर्षा कुमारी – ८७.६०:, अनन्या मिश्रा – ८७.६०:, समृद्धि – ८६.८०:, प्रज्ञा राज – ८६.४०: एवं वसुन्धरा तिवारी – ८४.६०: हाईस्कूल में सम्मानित होने वाले छात्रध्छात्रायें : श्रेया दीक्षित– ६१.१७:, सचेन्द्र पाल – ६०.३३:, सक्षम शर्मा – ८६.८३:, श्रेया शुक्ला– ८६.६७: एवं आराध्य शुक्ला – ८७.६७: इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी एवं बालिका विभाग की प्राचार्या श्रीमती मधु त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में छात्र/छात्राओं से कहा कि सफलता को व्यापक रूप से देखें। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अनुशासन और परिश्रम इसे सरल बना देते हैं।

अतिक्रमण हटाने पर व्यापारियों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस

मोहम्मदी संवाददाता। कस्बा में गोला रोड बरवर चौराहे से बिना पूर्व सूचना के नगर पालिका, तहसीलदार और कस्बा इंचार्ज टीम के साथ पहुंचकर सड़क से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करते ही व्यापारियों ने कडा विरोध जताया है। बुधवार को शाम ५ बजे करीब तहसीलदार अरुण कुमार, ई ओ जेपी मौर्य, कस्बा इंचार्ज अखिलेश सिंह दलबल के साथ पहुंच कर बरवर चौराहे से गोला रोड पर सड़क किनारे अतिक्रमण को जेसीबी से ढहाना शुरू कर दिया व्यापारियों ने अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सी एच सी रोड से लेकर बाजार गंज तक अतिक्रमण होने के चलते मरीजों को समय पर एंबुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है वहां से आक्रमण हटाने की मांग की है।

जर्जर भवन में छात्राओं की जिंदगी पर संकट, हाईकोर्ट सख्त

लखनऊ। राजधानी के हुसैनगंज स्थित ऐतिहासिक चुटकी भंडार बालिका इंटर कॉलेज से जुड़ा प्रकरण अब छात्राओं की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही तथा संवैधानिक दायित्वों से संबंधित अत्यंत गंभीर जनमहत्व का विषय बन चुका है। लगभग एक शताब्दी पुराने इस ऐतिहासिक बालिका विद्यालय के जर्जर एवं अत्यंत खतरनाक भवन में सैकड़ों छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियां निरंतर संचालित किए जाने के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार पाण्डेय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के समक्ष योजित जनहित याचिका विजय कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य दाखिल की गई । मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर एवं माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वीर राघव चौबे और गिरीश तिवारी ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादीगण की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अतिरिक्त अधिवक्ता डी.के. सिंह चौहान, इन्द्र प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार पाण्डेय, महेन्द्र बहादुर सिंह, शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं विकास सिंह उपस्थित रहे। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को किसी साधारण प्रशासनिक विवाद के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे सीधे तौर पर छात्राओं के जीवन एवं सुरक्षित शिक्षा के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा गंभीर प्रश्न माना। न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ श्री राकेश कुमार तथा लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधिशासी अभियंता श्री सत्येन्द्र नाथ न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि न्यायालय इस प्रकरण में प्रशासनिक जवाबदेही को प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित करना चाहता है। सुनवाई के दौरान

न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि चुटकी भंडार बालिका इंटर क लेज का भवन सौ वर्ष से अधिक पुराना है तथा उसकी स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। जनहित याचिका में यह प्रार्थना की गई थी कि भवन की खतरनाक स्थिति को देखते हुए विद्यालय परिसर में तत्काल प्रभाव से शैक्षणिक गतिविधियां बंद की जाएं तथा छात्राओं को निकटवर्ती सुरक्षित विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए। न्यायालय के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा विद्यालय भवन का निरीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट २८ अप्रैल २०२६ को दाखिल अनुपूरक शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। निरीक्षण रिपोर्ट में भवन में अत्यंत गंभीर संरचनात्मक दोष पाए जाने की पुष्टि की गई। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि भवन की अधिकांश दीवारों में गंभीर दरारें हैं, छत ईंट निर्मित है तथा भवन की प्रभावी मरम्मत की कोई संभावना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण भवन छात्राओं एवं कर्मचारियों के लिए असुरक्षित पाया गया। न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा कक्ष संख्या ११, १३, १७ एवं १८ पूर्व में ही बंद की जा चुकी थीं। न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब भवन की स्थिति इस प्रकार असुरक्षित पाई गई है, तब अन्य कक्षाओं में भी शैक्षणिक गतिविधियां संचालित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपने महत्वपूर्ण आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर विद्यालय परिसर में समस्त शैक्षणिक गतिविधियां पूर्णतः बंद कराई जाएं। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि विद्यालय की सभी छात्राओं को अन्य सुरक्षित एवं उपयुक्त विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को पहले अपनी पसंद के वैकल्पिक विद्यालयों में प्रवेश का प्रयास करने की स्वतंत्रता होगी तथा यदि उन्हें प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई हो, तो वे जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्राओं को सुरक्षित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश उपलब्ध कराया जाए तथा यथासंभव अभिभावकों की प्राथमिकता वाले विद्यालयों को वरीयता दी जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त शिक्षण संस्थान एक राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था है, जिसकी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। न्यायालय ने निर्देशित किया कि शिक्षकों एवं गैर–शिक्षण कर्मचारियों के सेवा हित, सेवा निरंतरता एवं अन्य वैधानिक लाभों को संरक्षित रखा जाए तथा राज्य सरकार की नीति एवं विधि के अनुसार उनके पुनर्स्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। न्यायालय ने विद्यालय प्रबंधन समिति को यह स्वतंत्रता भी प्रदान की कि वह विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण हेतु "अलंकार योजना" के अंतर्गत राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि यदि प्रबंधन समिति विस्तृत भवन योजना एवं निर्माण लागत के साथ कोई आवेदन प्रस्तुत करती है, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी उसे विधि के अनुसार विचारार्थ ग्रहण करेंगे। मामले को १६ जुलाई २०२६ को पुनः सूचीबद्ध करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, न्यायालय ने उस दिन उपस्थित अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति को आगामी आदेश तक के लिए छूट प्रदान की। यह उल्लेखनीय है कि चुटकी भंडार बालिका इंटर कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, महिला शिक्षा और सामाजिक चेतना की ऐतिहासिक धरोहर है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष १६२१ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई थी। प्रसिद्ध गांधीवादी लेखक रामनाथ सुमन द्वारा लिखित पुस्तक "उत्तर प्रदेश में गांधी" के अनुसार, महात्मा गांधी ने वर्ष १६२० में लखनऊ प्रवास के दौरान महिलाओं से आह्वान किया था कि वे भोजन बनाने से पूर्व "एक चुटकी आटा" स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग रखें। महिलाओं के इसी योगदान से एकत्र धनराशि से बालिका शिक्षा को समर्पित "चुटकी भंडार स्कूल" की स्थापना की गई, जो समय के साथ विकसित होकर आज चुटकी भंडार बालिका इंटर क लेज के रूप में स्थापित हुआ। याचिकाकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार पाण्डेय ने इस महत्वपूर्ण जनहित याचिका में प्रभावी पैरवी करने वाले अधिवक्ता वीर राघव चौबे के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता वीर राघव चौबे ने मात्र एक रुपये के सांकेतिक शुल्क पर इस जनहित विषय को लड़ने का दायित्व स्वीकार किया तथा छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा के संवैधानिक अधिकार की रक्षा हेतु अत्यंत समर्पण एवं संवेदनशीलता के साथ न्यायालय में पक्ष रखा। चुटकी भंडार बालिका इंटर कॉलेज प्रकरण अब केवल एक जर्जर भवन का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह बालिका शिक्षा, विरासत संरक्षण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से जुड़ा एक ऐतिहासिक जनहित प्रकरण बन चुका है। यह मामला स्पष्ट करता है कि जब प्रशासनिक तंत्र अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में विफल हो जाता है, तब न्यायपालिका नागरिकों विशेषकर छात्राओं के जीवन एवं सुरक्षित शिक्षा के अधिकार की रक्षा हेतु निर्णायक हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होती है।

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देशभर में मेडिकल स्टोर बंद, १५ लाख से अधिक दवा कारोबारियों की हड़ताल

लखनऊ। दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री, ई–फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की मनमानी और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के बढ़ते दबदबे के विरोध में बुधवार को देशभर में मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी बंद में १५ लाख से अधिक केमिस्ट और दवा विक्रेताओं ने समर्थन जताया। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में मेडिकल स्टोर बंद रहने से लोगों को दवाएं लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर और आपातकालीन सेवाओं को बंद से अलग रखा गया, ताकि मरीजों को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनी रहे। दवा कारोबारियों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त सत्यापन और डॉक्टर की वैध पर्ची के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री के जरिए प्रतिबंधित और प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं भी

आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। दवा विक्रेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बड़ी ई–फार्मेसी कंपनियां भारी छूट देकर छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर रही हैं। उनका कहना है कि २० से ५० प्रतिशत तक की छूट देकर ऑनलाइन कंपनियां बाजार पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे पारंपरिक मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। लखनऊ के दवा व्यापारियों ने भी बंद को समर्थन देते हुए कहा कि यह केवल व्यापार का मुद्दा नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। व्यापारियों के अनुसार बिना फार्मासिस्ट सत्यापन के अ नलाइन दवा बिक्री गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। वहीं, केंद्र सरकार और औषधि नियंत्रण विभाग ने आश्वासन दिया कि बंद के बावजूद आवश्यक दवाओं की उपलब्धता प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। कुछ राज्यों के फार्मेसी संगठनों ने सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए बंद से दूरी भी बनाई।

संविदा कर्मचारियों ने लंबित मानदेय भुगतान को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

बाराबंकी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों ने लंबित मानदेय भुगतान को लेकर बुधवार को तीसरे दिन भी सीएचसी बनीकोडर समेत जिलेभर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध उप्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर चल रहे आंदोलन में संविदा चिकित्सक, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, सीएचओ, पैरामेडिकल स्टाफ, बीपीएम और बीसीपीएम समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रांतीय अध्यक्ष ठाकुर मयंक प्रताप सिंह के निर्देश तथा जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। जिला महामंत्री डॉ. रईस खान और मंडल अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेन्द्र भारती ने बताया कि मार्च और अप्रैल २०२६ का मानदेय अब तक जारी नहीं हुआ है, जिससे

कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि २० मई तक भुगतान नहीं हुआ तो २१ मई से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। हालांकि जनहित को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है।

डाटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा में बोले सीएम योगी– लखनऊ को करें 'एआई सिटी' के रूप में विकसित

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े तीन अहम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि डाटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। इसकी शुरुआत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र से की जा सकती है जहां बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने टाटा समूह समेत बड़ी टेक कंपनियों से संवाद कर लखनऊ को 'एआई सिटी' के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। प्रोजेक्ट गंगा' यानी गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क ॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुने गए डिजिटल उद्यमियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण करने वाली कंपनियां भी इन युवाओं का उपयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। अ प्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने डिजिटल उद्यमियों को शुरुआत से ही इंसेंटिव देने को कहा। प्रोजेक्ट गंगा के तहत १० हजार से अधिक युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा, जिससे ५० हजार प्रत्यक्ष और १ लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। २० लाख से अधिक घरों को फाइबर आधारित हाई–स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक को ५ लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। योजना में ५०: महिला उद्यमियों

को जोड़ने का लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल २१ जिलों में पायलट के तौर पर शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन–हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाए। मंडियों में साफ–सफाई, रंगाई–पुताई, त्योहारों पर लाइटिंग, अतिक्रमण हटाने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न सुरक्षा के लिए प्रदेश को अभी से तैयार रहना होगा। यूपी देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। २०२५–२६ में ३७२ लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। प्रदेश में ५५६ रोलर फ्लोर मिल्स हैं जिनकी क्षमता २१८. ४ लाख मीट्रिक टन है, लेकिन उपयोग सिर्फ १२६.४५ लाख मीट्रिक टन हो रहा है। समिति ने सुझाव दिया कि यूपी में पंजीत मिलों द्वारा राज्य के भीतर प्रसंस्करण के लिए खरीदे गए गेहूं पर मंडी शुल्क और विकास उपकर में छूट दी जाए, लेकिन यह छूट व्यापारिक गतिविधियों पर लागू न हो। बैठक में बताया गया कि यूपी की भौगोलिक स्थिति इसे समुद्री जोखिमों से सुरक्षित बनाती है। एक्सप्रेस–वे, एयरपोर्ट, ल जिस्टिक्स नेटवर्क और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर, एनआईटी प्रयागराज और ५० से अधिक इंजीनियरिंग संस्थानों के कारण विशाल तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध है। देश के लगभग सभी प्रमुख फाइबर नेटवर्क यूपी से होकर गुजरते हैं।

मसाला फिल्मों से कोर्टरूम ड्रामा तक, सोनाक्षी सिन्हा का फिल्मी सफर

मुम्बई। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर में कई अलग–अलग तरह की फिल्में की हैं। इन दिनों वह अपनी आने वाली फिल्म 'सिस्टम' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने आईएएनएस से अपने फिल्मी सफर, पुराने किरदारों और बदलती पसंद के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि समय के साथ न सिर्फ उनके काम करने का तरीका बदला, बल्कि अब वह अपने रोल्स को पहले से ज्यादा सोच–समझकर चुनती हैं। आईएएनएस से बात करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने अपने शुरुआती दौर की फिल्मों को याद किया। उन्होंने कहा जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा थी जो कलरफुल, मनोरंजन से भरपूर और पूरी तरह मसाला अंदाज की होती थीं। 'आर. राजकुमार' और 'राउडी राठौर' जैसी फिल्मों में काम करके काफी मजा आया। उस समय मैं अपने करियर के ऐसे दौर में थी, जहां दर्शक मुझे उसी अंदाज में देखना पसंद करते थे।" उन्होंने कहा, "मैंने इन किरदारों को पूरी ईमानदारी और खुशी के साथ निभाया। लेकिन हर कलाकार के जीवन में अलग–अलग चरण आते हैं और हर दौर में दर्शकों की पसंद और इंडस्ट्री की मांग भी बदलती रहती है। अभिनेत्री ने आगे कहा अब मैं अपने करियर के ऐसे मोड़ पर हूं, जहां मैं सिर्फ वही काम करना चाहती हूं, जो मुझे अंदर से संतुष्टि देता हो। अब मैं खुद को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में देखती हूं, जो हर तरह के किरदार निभा सके। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे ऐसी कलाकार के रूप में देखें, जिसे किसी भी तरह की फिल्म में रखा

जा सके। अब मैं सिर्फ वही काम कर रही हूं, जो मैं सच में करना चाहती हूं।" सोनाक्षी ने अपने पुराने फिल्मी सफर को लेकर भी आभार जताया। उन्होंने कहा, "अगर मैंने शुरुआत में मसालेदार फिल्में नहीं की होतीं, तो शायद आज मुझे ऐसे अलग और गंभीर किरदार निभाने का मौका नहीं मिलता। मुझे फिल्मों ने दर्शकों का प्यार, पहचान और समर्थन दिलाया। लोगों के प्यार की वजह से ही आज मैं अपने मन के किरदार को चुन पा रही हूं और नई तरह की कहानियों का हिस्सा बन रही हूं।" अपनी आने वाली फिल्म 'सिस्टम' के बारे में बात करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि यह फिल्म उनके लिए काफी खास है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें वह पहली बार वकील की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में अभिनेत्री एक स्टेनोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी। 'सिस्टम' फिल्म २२ मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

अहाना कुमरा ने माता–पिता के दिन को बनाया खास

मुम्बई। अभिनेत्री अहाना कुमरा हाल ही में परिवार के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का लाइव मैच देखने स्टेडियम पहुंचीं, जहां उन्होंने खास अंदाज में डबल सेलिब्रेशन किया। बुधवार को अभिनेत्री ने आईपीएल मैच की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में अभिनेत्री परिवार संग फुर्सत के पल बिताती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अहाना ने बताया कि यह मौका उनके पिता के ७५वें जन्मदिन और माता–पिता की शादी की सालगिरह का था। इस खास अवसर को यादगार बनाने के लिए वे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचीं। अहाना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा मेरे पापा के जीवन के ७५ साल पूरे हो गए। इस खास मौके पर हमने

उनकी पुरानी इच्छा पूरी की। उनकी तमन्ना थी कि वे एक बार स्टेडियम में बैठकर लाइव क्रिकेट मैच देखें। ७५वें जन्मदिन के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान र यल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला देखना हम सभी के लिए बेहद शानदार और यादगार अनुभव रहा। अहाना ने बताया कि लाइव मैच के दौरान बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले शानदार छक्के देखना उनके पिता के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने लिखा इसी के साथ मेरे माता–पिता की सालगिरह का जश्न भी था, जिसने इस दिन को हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल कर दिया। इतने बड़े आयोजन में माता–पिता की सुविधा का ध्यान रखने और आफ्टर पार्टी के खास इंतजाम के लिए भी अभिनेत्री ने ड्रीमसेटगो की टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, "मेरे पापा उस दिन छोटे बच्चे की तरह खुश नजर आए। कुछ दिन जिंदगी में हमेशा के लिए याद बन जाते हैं और सच में, जब हम अपने माता–पिता को खास महसूस कराने के लिए छोटी–सी कोशिश भी करते हैं, तो हर बच्चे का दिल खुशी से भर जाता है। बता दें कि अभिनेत्री अहाना कुमरा एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। उनके पिता सुशील कुमरा ल्यूपिन लिमिटेड (दवा क्षेत्र की जानी–मानी कंपनी) के पूर्व उपाध यक्ष हैं, जबकि मां सुरेश कुमरा वाराणसी की पूर्व डीएसपी रह चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक